# भारत का राजपत्र The Gazette of India

## ग्रसाघ । रण

## EXTRAORDINARY

भाग **II**—-अण्ड 3—उपलज्ज (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) 11 7/7 (137)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

HO 144

नई विल्ली, सोमवार, मार्च 25, 1974/चंत्र 4, 1896

No. 144]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1974/CHAITRA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या ही जासी हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सकी।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate complication.

#### MINISTRY OF LABOUR

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March 1974

S.O. 206(E).—Whereas the Central Government is of opinion that any employment under the Hindustan Construction Company Limited in the Haldia Dock Project (hereinafter referred to as the said employment) is essential for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 119 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby declares the said employment to be an employment to which rule 119 of the said rules applies.

[No. F. S-42025/5/74/II-LR.I]

## श्रम मंत्रालय

## ग्रिषिसंचमा

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1974

का० ग्रा० 206(ग्र).—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि हात्ष्डिया डाक परियोजना में हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के श्रधीन कोई नियोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियोजन कहा गया है), समृदाय के जीवन के लिये ग्रावण्यक प्रदाय ग्रीर सेवाए बनाये रखने के लिये ग्रावण्यक है;

श्रतः , श्रव केन्द्रीय सरकार, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 119 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त गियतों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियोजन को ऐसे नियोजन के रूप में घोषित करती है, जिसे उक्त नियमों का नियम 119 लागू होता है।

[मं॰ फा॰ एस॰-42025/5/74/H-एल॰ ग्रार॰ 1]

#### ORDER

## New Delhi, the 25th March 1974

S.O. 207(E).—Whereas the Central Government have, by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S-42025/5/74-LR.I, dated the 25th March, 7974, declared employment under the Hindustan Construction Company Limited in the Haldia Dock Project to be an employment to which rule 119 of the Defence of India Rules, 1971, applies;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 119 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby regulates the wages in respect of persons who are workmen as defined in clause (s) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and are entired in sub-anniholyment in the manner specified in the Schedule annexed here.

#### SCHEDULE

The existing wages of all categories of workmen shall be increased by Rs. 15 per head per month;

Provided that this increase shall not count towards any other benefit, statutory or otherwise, and subject to subsequent adjustment in terms of the award of the National Industrial Tribunal set up by the order of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3193 dated the 1st December, 1973 in the industrial dispute referred to that Tribunal by the said order.

[No. F. S-42025/5/74/II-LR.I]

N. P. DUBE, Addl. Secy.

# नई दिल्ली, 25 मार्च 1974

## कार्ले क

का॰ आ॰ 207(का):--यतः केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का श्रधिसृचना सं॰ एस--42025/5/74--एल श्रार 1 तारीख 25 मार्च, 1974 द्वारा, हाल्डिया डाक परियोजना में हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के श्रयीन निर्माजन की ऐसे निर्योजन के कृप में घोषित किया है जिसे भारत रक्षा नियम, 1971 का नियम 119 लागू होता है;

श्रतः, श्रवः भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 119 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त णिवतयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय परकार, उन व्यक्तियों की बाबत, जो श्रीशोगिक विवाद श्रिधिनियम, 47 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित कर्मकार है श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्देश्ट रीति से ऐसे नियोजन में लगे हुए हैं, मजदूरी विनियमित करती है।

# ग्रनुम<del>ूषी</del>

"सभी प्रवर्गों के कर्म कारों की विद्यमान भजदूरी में प्रतिमास प्रति व्यक्ति 15 र० की वृद्धि की जाएगी: परन्तु यह बृद्धि कि नी अन्य फायदे कानूनी या अन्यथा, में नहीं गिनी जाएगी और भारत सरकार के कृषि मं ग्रान्य के आदेश सं कार्य आत 3493 तारीख 1 दिसम्बर, 1973 द्वारा गठित राष्ट्रीय औद्योगिक भूभितिकरण के, जैन्दित आदेश द्वारा के अधिकरण को निदिष्ट श्रीद्योगिक विवाद में, पंचाट के अनुसार पश्चातवर्ती करार के अधीन होगी। '

> [सं० फा० एस-42025/5/74 II-एल म्रार 1] एन०पी०दूबे, म्रापर सचित्र।

